सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-31 अंक-04 22 फरवरी, 2016 | मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती | कुल पृष्ठ 8 | मूल्य : 2 रुपये

जीवनरक्षक दवाओं पर आयात शुल्क छूट हटाने के केन्द्र सरकार के फैसले के खिलाफ एसयूसीआई(सी) ने किया प्रतिवाद

एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 7 फरवरी को जारी बयान में कहा :

केन्सर के इलाज में काम आने वाली सहित 75 जीवनरक्षक दवाओं पर आयात शुल्क में मिलने वाली छूट आइन्दा वापस लेने के केन्द्र सरकार के जनविरोधी फैसले का हम कड़ा विरोध करते हैं। इसके नतीजे के तौर पर इन आवश्यक दवाइयों पर इसके बाद से एक्साइज और आयात शुल्क 22 प्रतिशत से ज्यादा लगा करेगा। इस प्रकार ये दवाइयां बेहद महंगी हो जायेंगी। जहां ये दवाइयां आम मेहनतकश लोगों को मुफ्त मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वहीं घोषित तौर पर देशी दवा कम्पनियों के स्वार्थ में लिया गया यह कदम या तो इन दवाओं को खरीदने में मरीजों का कचूमर निकाल देगा या इलाज का बढ़ा हुआ खर्च वहन करने में असमर्थ होने पर तड़प-तड़प कर मरने के लिए छोड़ देगा। जो भी थोड़ा बहुत जनकल्याण था सत्ता में आने के बाद बीजेपी को उसमें बाकायदा कटौती करने की आदत सी पड़ गई है। जबकि बैंकों का बकाया कर्ज ब्याज सहित माफ करने सहित औद्योगिक घरानों और कारपोरेटों को असीम छूट और कर्जमाफी दे रही है।

हम दुखी जनसाधारण और साथ ही डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हुए अन्य सब लोगों से आह्वान करते हैं कि इस मौके पर उठ खड़े हों और इस गैरजनवादी और निरंकुश फैसले के खिलाफ जोरदार संगठित आन्दोलन खड़ा करें।

बीजेपी ने दिखाये अपने फासीवादी जहरीले दांत

दिल्ली की जेएनयू में घटी घटना और इसके बाद के हालात पर एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉ. प्रभास घोष ने 18 फरवरी को निम्नलिखित बयान जारी किया : सबसे पहले में बीजेपी और इसके संगठनों के गुण्डों द्वारा जेएनयू के छात्रों पर किये गये कायराना हमले की अपनी पार्टी की तरफ से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। यह अब स्पष्ट हो चुका है कि जेएनयू के अन्दर जनवादी वातावरण के खिलाफ मामला खड़ा करने के लिए शासक बीजेपी जीजान से बहाना खोजने के प्रयास में जुटी हुई थी ताकि उसकी आड़ में इस पर हमला किया जा सके। 9 फरवरी की घटना ने जहाँ किसी हाशिये पर पडे छात्र ग्रुप द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाये गए जिसने बीजेपी को चिरअपेक्षित बहाना दे दिया अपने फासीवादी जहरीले दांत दिखाने का। जिस तरह जेएनयू छात्र यूनियन अध्यक्ष की आनन फानन में गिरफ्तारी, राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर उसके खिलाफ केस दायर करने में अप्रत्याशित जल्दबाजी, छात्रों और आलोचकों पर राष्ट्रद्रोही होने का लेबल लगा देना और कुछ बीजेपी वकीलों का भद्दा आचरण जो पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर पत्रकारों और छात्र नेता का कोर्ट परिसर में पीटने की हद तक चले गये, ये सब बिन्दु इशारा करते हैं कि यह आरएसएस-बीजेपी के शीर्ष नेताओं द्वारा रचा गया एक निश्चित षडयंत्र था।

यह दिलासा देने वाली और उत्साहवर्धक बात है कि देश का बुद्धिजीवी तबके और हमारे देश के जनवाद पसंद व सही सोच रखने वाले लोगों का बड़ा तबका संघ परिवार के द्वेषपूर्ण घृणित षडयंत्र के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और मजबूती से छात्रों के साथ खड़ा है। तमाम वामपंथी छात्र संगठनों के खिलाफ नफरत फैलाने का बीजेपी का अभियान मांग करता है कि छः वाम पार्टियों के गठजोड़ द्वारा संयुक्त आन्दोलन चलाया जाये।

इस बात पर भी गौर किया जाये कि कॉंग्रेस का पिछला रिकार्ड साफ तौर पर दर्शाता है कि न तो यह एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और न ही यह जनवादी पार्टी है। हमारा दृढ़ मत है कि यह आन्दोलन को छः वामपंथी पार्टियों के नेतृत्व में ही संगठित किया जाना चाहिए।

जेएनयू की घटना पर ऑल इण्डिया डीएसओ का बयान

जेएनयू में घटी घटना पर ऑल इण्डिया डीएसओ के महासचिव कॉमरेड अशोक मिश्रा ने 13 फरवरी को जारी प्रैस बयान में कहा : हाल ही में 9 फरवरी, 2016 को कुछ बाहरी तत्वों द्वारा दिल्ली की जेएनयू में एक फंक्शन आयोजित किया गया और कथित तौर पर वहां ऐसे नारे लगाये गये जो देश-विरोधी थे। हम इस कार्रवाई की कड़ी निन्दा करते हैं और हमारा संगठन ऑल इण्डिया डीएसओ इससे या कहीं ऐसे फंक्शन से किसी तरह भी जुड़ा हुआ नहीं है; उल्टे ऑल इण्डिया डीएसओ हमारे देश के आजादी आन्दोलन की गैरसमझौतावादी धारा के संघर्ष को समर्थन करता है। लेकिन उन आपत्तिजनक नारों के बहाने दक्षिणपंथी ताकतों ने तमाम वाम छात्र संगठनों के खिलाफ घृणा प्रचार अभियान छेड़ दिया है और उन ताकतों और बीजेपी सरकार के इशारे पर पुलिस छात्रावासों में वामपंथियों को प्रेत करार देकर उनके पीछे पड़ने लगी है। हम इसका कड़ा प्रतिवाद करते हैं।

सरकार ने बजट में उनकी मांगें नहीं मानी तो आर-पार की लड़ाई लड़ेंगी आंगनवाड़ी कर्मी

नई दिल्ली : 15 फरवरी को आंगनवाड़ी कर्मियों की फैडरेशनों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर देश के कोने-कोने से 1 लाख के लगभग आंगनवाड़ी वर्करों और हैल्परों ने संसद पर विशाल प्रदर्शन किया। संसद मार्ग पर पहुंच कर यह प्रदर्शन विरोध सभा में तब्दील हो गया। इस मोर्चे में एआईयूटीयूसी, सीआईटीयू, एटक, एआईसीसीटीयू, एचएमएस और इंटक से सम्बन्धित आंगनवाड़ी कर्मियों की फैडरेशनें शामिल हैं। फैडरेशनों के प्रतिनिधिमण्डल ने वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) का बजट आवंटन बढ़ाकर कम से कम 36 हजार करोड़ रुपये किया जाये ताकि आईसीडीएस लाभार्थियों के लिए बुनियादी सेवाएं, अच्छी गुणवत्ता का पूरक पोषाहार तथा वर्करों व हैल्परों को बेहतर जीवनदशा सुनिश्चित की जा सके। आईसीडीएस का किसी भी रूप में निजीकरण न किया जाये। आईसीडीएस को वेदांता जैसे कारपोरेट व इस्कॉन जैसे गैर सरकारी संगठनों को न सौंपा जाये। आंगनवाड़ी वर्करों व हैल्परों को क्रमशः तृतीय व चतुर्थ श्रेणी का सरकारी कर्मचारी बनाया जाये। नियमितीकरण लंबित रहने तक कम से कम 18,000 रुपये मासिक वेतन और 3000 रुपये पेन्शन सहित सामाजिक सुरक्षा

(शेष पृष्ठ 5 पर)

दिल्ली : 15 फरवरी को आंगनवाड़ी कर्मी फैडरेशनों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर संसद पर हुई विशाल रैली को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड अचिंत्य सिन्हा

दूसरा झारखण्ड राज्य एआईएमएसएस सम्मेलन आयोजित

जमशेदपुर (झारखण्ड) : जमशेदपुर में 31 जनवरी से 1 फरवरी तक ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) का झारखण्ड राज्य का दूसरा सम्मेलन आयोजत किया गया। विभिन्न जिलों से आई प्रतिनिधियों का एक सुसज्जित जुलूस शहर के साकची आमबगान से साकची गोलचक्कर, बसंत सिनेमा व आई अस्पताल होते हुए आमबगान मैदान पहुंचा। जुलूस का नेतृत्व संगठन की झारखंड राज्य अध्यक्ष श्रीमती लिली दास, सचिव केया डे, कोषाध्यक्ष चंदना बनर्जी, उपाध्यक्ष रेबा महतो, सबिता बोस, सह सचिव सोनोका महतो ने किया। खुला अधिवेशन सिदगोड़ा स्थित टाउन हॉल में आयोजित किया गया। यहां पर झारखंड के नामचीन बुद्धिजीवियों के अलावा, संगठन की सर्वभारतीय अध्यक्ष कॉमरेड छाया मुखर्जी व अन्य राज्यों से आई हुई संगठन की नेत्रियों ने सभा को संबोधित किया। सभा के दौरान गीत, नाटक आदि कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। स्वागत समिति के चेयरमैन व जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज के प्राचार्य जीतेंद्र कुमार ने उद्घाटन भाषण दिया। सभा की अध्यक्षता संगठन की अध्यक्ष लिली दास ने की। राज्य के जाने-माने बुद्धिजीवियों के अलावा एआईएमएसएस अध्यक्ष कॉमरेड छाया मुखर्जी ने खुले अधिवेशन को सम्बोधित किया। कॉमरेड मुखर्जी ने अपने भाषण में कहा कि आज हम एक भयावह संकट के दौर से गुजर रहे हैं। झारखंड सहित पूरे देश भर में महिलाओं पर शोषण, अत्याचार, जुल्म का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में झारखंड के विभिन्न जिलों में लगातार महिलाओं पर हुए अत्याचारों की खबरें सुर्खियों में रही हैं। आज महिलाएं घर-बाहर, गली चौराहे कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वह ईंट-भट्ठा में काम करने वाली महिला हो या फिर दफ्तर की मेज-कुर्सी पर बैठ कर काम करने वाली महिला, हर दिन हर रोज वे शारीरिक व मानसिक शोषण का शिकार हो रही हैं। इसके साथ जुड़ गया है भूमंडलीकरण का दौर। भूमंडलीकरण के साथ आया है सेक्स टूरिज्म, ब्यूटी कॉन्टेस्ट और फैशन शो की होड़। नारी बिक रही है, उसका अंग-अंग निलाम हो रहा है, ग्लोबल, कॉरपोरेट और बहुर्राष्ट्रीय पूंजी के मुनाफे को सुनिश्चित करने के लिए। मीडिया में लगातार हिंसा व यौनता परोसी जा रही है। शराब की दुकानों के लाइसेंस धड़ल्ले से दिये जा रहे हैं। इससे पूरे समाज में नशाखोरी, नैतिक पतन व अश्लीलता व्यापक रूप से फैल रही है। इसका सीधा असर पड़ रहा है महिलाओं पर। अत्याचार, बलात्कार, यौन उत्पीड़न में तीव्र बढ़ोतरी हो रही है। इस स्थिति में नारी समाज को संघर्ष के लिए आगे आना होगा। इसी संघर्ष की बदौलत उसे उसकी खोयी हुई मर्यादा, अधिकार व आत्मसम्मान दुबारा हासिल होगा। उन्होंने बढ़ती अश्लीलता, बच्चियों

जमशेदपुर में झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों से आई प्रतिनिधियों का विशाल जुलूस

व महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध-अत्याचार और महिलाओं के शारीरिक व मानसिक शोषण के खिलाफ जोरदार आन्दोलन करने का आह्वान किया।

अन्य वक्ताओं में शामिल थे संगठन की प्रांतीय सचिव केया डे, उपाध्यक्ष रेबा महतो, सबिता बोस, सह सचिव सोनोका महतो। प्रख्यात गायक उदयन बोस, अजय राय और साथियों ने गीत प्रस्तुत किये। करीम सिटी कॉलेज की स्पार्क टीम ने 'औरत' नाटक प्रस्तुत किया। श्यामल सुमन ने कविता पाठ किया। शोक प्रस्ताव का पाठ कोषाध्यक्ष चंदना बनर्जी ने किया।

1 फरवरी को धतकीडीह कम्यूनिटी सेण्टर में प्रतिनिधि अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अवसर पर लगभग 200 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में देश की वर्तमान आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक परिस्थिति का विश्लेषण किया गया। इससे संबंधित एक प्रारूप पानमोनि सिंह ने प्रस्तुत किया, जिस पर प्रतिनिधियों ने कई संशोधन प्रस्तुत किये। बाद में इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके उपरांत संगठन की सचिव केया डे ने सांगठनिक रिपोर्ट पेश की। सभा में सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किये गये।

मूल रूप से महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर रोक लगाने, शराब और नशाखोरी पर पूर्ण पाबंदी लगाने, अश्लील सिनेमा साहित्य पर रोक लगाने, दहेज हत्या, भ्रूण हत्या पर रोक लगाने, समान काम के लिए समान वेतन लागू करने, नारी तस्करी, नारी उत्पीड़न पर रोक लगाने, महिलाओं व छात्राओं की सुरक्षा की गारंटी करने की मांग को लेकर आगामी दिनों प्रखंड व अनुमंडल स्तर से लेकर राज्य स्तर पर जुझारू व व्यापक आंदोलन निर्माण करने की योजना तैयार हुई।

सम्मेलन के उपरांत 21 सदस्यीय मजबूत नई राज्य कमिटी चुनी गई। इसकी अध्यक्ष पानमोनि सिंह, उपाध्यक्ष सबिता बोस, सोनोका महतो, चंदना बनर्जी, रेबा महतो, मालती देवी, सचिव केया डे, कोषाध्यक्ष अशोका मंडल, सचिवमंडली सदस्य संतोषी महतो, संध्या पांडेय, विमला साहू, उपासिनी सरदार, दुखनी माझी, चाईना महतो, कार्यकारिणी सदस्य: पुष्पो महतो, अंबिका महतो, निर्मला शर्मा, विमला सिंह, रितु खालखो, कमलिनी सरदार चुनी गई।

अंत में सभा के मुख्य वक्ता व संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष छाया मुखर्जी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन के दौरान जो जोश और उत्साह महिलाओं में देखने को मिला, उसे संजो कर रखना चाहिए और झारखंड में महिलाओं पर बढ़ते उत्पीड़न के खिलाफ एक जुझारू आंदोलन का निर्माण होना चाहिए। इसी क्रम में संगठन का भी विस्तार होगा और महिलाएं खुद ही अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगी। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई पुरुषों के खिलाफ नहीं बल्कि पुरुष प्रधानता के खिलाफ है। जो समाज यह मानसिकता पैदा करता है, जो समाज शोषण पर आधारित है, उस वर्तमान पूंजीवादी समाज को परिवर्तित किये बिना महिला मुक्ति संभव नहीं।

सम्मेलन के मुख्य अतिथि एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के झारखंड राज्य सचिव कॉमरेड रबीन समाजपति ने नई कमिटी को बधाई देते हुए कहा कि झारखंड में महिलाओं पर जितनी समस्याएं बढ़ रही हैं, उतना महिला संगठन सक्रिय नहीं है। झारखंड की महिलाओं को एआईएमएसएस से बहुत अपेक्षाएं है, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर खरी उतरेंगी। क्रांतिकारी गीत से सभा का समापन हुआ।

31 जनवरी को एआईएमएसएस के दूसरे झारखण्ड राज्य सम्मेलन के खुले अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए एआईएमएसएस अध्यक्ष कॉमरेड छाया मुखर्जी

वक्त का तकाजा

शिक्षा खतरे में है, अब वक्त आ गया है शिक्षा को बचाने के लिए संघर्ष करने का

भारत में शिक्षा नए तरीके से जबरदस्त हमलों की चपेट में है। पहले भी कई अवसरों पर हम दर्शा चुके हैं कि वस्तुत: आजादी के समय से ही आम जनता के लिए दी जाने वाली शिक्षा लगातार हमलों का शिकार हो रही है चाहे वह हमला शिक्षा की विषयवस्तु पर हो या शिक्षा प्रदान करने के तरीकों पर ही क्यों न हो। हमारे देश के आजादी आंदोलन के शहीदों और मनीषियों ने सभी के लिए सार्वभौमिक लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक शिक्षा का सपना देखा था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा शिक्षा में कटाती किए जाने, पाठयक्रम में हानिकारक बदलाव लाने या अकेडमिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने के तमाम प्रयासों का विरोध किया था। आजादी के बाद कुछ समय के लिए जनमत के दबाव में तथा गौरवपूर्ण आजादी आंदोलन के प्रभाव के कारण शासक भारतीय पूँजीपति वर्ग जिनके हाथों में आजादी के बाद सत्ता आई थी उन्होंने सरकारी संरक्षण में प्रदान की जा रही शिक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन जैसे ही भारतीय शासक वर्ग मरणासन्न विश्व-पूँजीवाद का एक अभिन्न अंग होने के कारण पहले से ही संकटग्रस्त भारतीय पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिक आक्रामक हुआ तो वह दो तत्वों से अत्यधिक भयभीत था। एक था कि इस संकटग्रस्त पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर लगातार घट रहे थे और शासकवर्ग के लिए शिक्षित बेरोजगारों की संख्या को बढ़ने देना भी खतरनाक था। एक सुशिक्षित दिमाग हमेशा यह जानने का इच्छुक होगा कि आखिर रोजगारों में हो रहे इस ह्रास का कारण क्या है? इसका कारण यह था कि जैसे-जैसे संकट और अधिक गहराता जा रहा था, शासक वर्ग ने लगातार इसका बोझ जनता पर डाल दिया जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी, गरीबी तथा इससे जुड़ी हुई सभी समस्याओं के खिलाफ़ जनाक्रोश स्वाभाविक तौर पर बढ़ता जा रहा था। अगर शोषित जनता को सही राजनैतिक चेतना हासिल हो जाए तो जनता का बढ़ता असंतोष और आक्रोश सही दिशा प्राप्त कर लेगा और इस शोषणकारी पूँजीवादी व्यवस्था के अस्तित्व को ही एक गंभीर खतरा पैदा कर देगा। शिक्षा वास्तविक तौर पर ही वह साधन थी जिसकी सहायता से जनता उस अपेक्षित राजनैतिक चेतना को हासिल कर सकती थी। इस प्रकार, शिक्षा पर चौतरफा हमला करना शासक वर्ग के लिए आवश्यक था।

सबसे पहले प्रहार हुआ उच्च शिक्षा पर। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए खुली घोषणा की गई, उच्च शिक्षा तक पहुँच को रोकने के लिए उस समय शासन कर रही तत्कालीन काँग्रेस-नीत सरकार सीट कटौती की योजना लेकर आई। शिक्षा को महंगी करने की नीति भी चरणबद्ध तरीके से लागू की गई। शिक्षा की विषय-वस्तु को कमजोर करने और इन्सान बनाने, चरित्र निर्माण करने तथा तार्किक मन विकसित करने के इसके सारतत्व को ही तबाह करने के लिए शुरूआती कदम के तौर पर धूर्तता से पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाया गया। तर्क शक्ति के आधार पर संघर्ष करने के जज़्बे की जगह है अंधानुकरण तथा दैववादी आत्मसमर्पण की मानसिकता को बढ़ावा दिया गया। आश्चर्यजनक रूप से प. बंगाल की सी.पी.आई.(एम)-नीत सरकार ने स्कूली शिक्षा के प्राइमरी स्तर पर अंग्रेजी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप मे समाप्त करके और नो डिटेंशन की नीति लागू करके काँग्रेस की केन्द्र सरकार के इस कदम को और भी बल प्रदान किया। इसके खिलाफ़ प्रतिरोध को रोकने के लिए शैक्षिक संस्थानों को वस्तुत: सरकार के उपंगों के रूप में परिवर्तित करके उन्होंने नग्नता से एकेडमिक स्वायत्तता को खत्म कर दिया। अंग्रेजी में अपनी कमज़ोरी के कारण छात्र उच्च शिक्षा में जाने के लिए स्वंय को अक्षम महसूस करने लगे। इसी वजह से प. बंगाल और देश के अन्य राज्यों में भी अंग्रेजी माध्यम वाले प्राइवेट स्कूल कुकुरमुत्तों की तरह पनपने लगे हैं।

अंतत: 'नई शिक्षा नीति' जिसे 1986 में राजीव गाँधी की काँग्रेस सरकार ने फ्रेम किया था शिक्षा को पण्य वस्तु अर्थात् बिकाऊ माल बनाने और शिक्षा का व्यापारीकरण करने के बुर्जुआ वर्ग के पूरे ताने-बाने को विस्तारपूर्वक सामने रख दिया। शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार करने का काम शिक्षाविदों व शिक्षा शास्त्रियों की बजाय बड़े-बड़े एकाधिकारी पूँजीपतियों को सौंपा गया। उन्होंने खुल्लमखुला घोषित कर दिया कि शिक्षा में निवेश एक फायदे का सौदा है और इसमें लाभ सुनिश्चित है। क्योंकि लोग अपनी पहुँच से भी बाहर जाकर अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार को लोगों को शिक्षित करने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना चाहिए। इसी वजह से धीरे-धीरे सरकारी स्कूलों का अवमूल्यन होता चला गया और प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ गई। देशी-विदेशी कॉरपोरेट घरानों की अगुवाई में निजी निवेशकों के शिक्षा व्यवसाय में मुनाफा कमाने के उद्देश्य ने निवेशकों के साथ-साथ शिक्षण संस्थानों को धन बटोरने में लगा दिया और उनके अध्यापकों और छात्रों को पैसा कमाने के काम में ज्यादा से ज्यादा धकेल दिया गया। दूसरी तरफ अत्यधिक महंगी होती जा रही शिक्षा ने गरीब-परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए। सब के लिए शिक्षा प्रदान करने की बजाय यह व्यवस्था अत्यधिक पक्षपातपूर्ण बन गई। इसमें एक तरफ थे वे अनगिनत आम छात्र जो गरीब परिवारों से आते हैं जिन्हें एम.एल.एल. अर्थात् न्यूनतम स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है, अर्थात् रोजगार आधारित व्यवसायिक शिक्षा के लिए शिक्षण का न्यूनतम स्तर यानी एम.एल.एल. निर्धारित किया गया जिसके साथ रोजगार-मुखी व्यवसायिक शिक्षा का लेबल लगा हुआ था जिसने थोड़ी-बहुत बची-खुची शिक्षा को भी कैरियर बनाने, स्वार्थपूर्ति के मकसद और नजरिए में पतित कर दिया। दूसरी तरफ, महंगे सुविधा प्राप्त डिजिटलाइज्ड स्कूल जहाँ पर सर्वोत्कृष्ट स्तर की शिक्षा अर्थात् ओ.एल.एल. मुट्ठी भर छात्रों को प्रदान की जाती है, ताकि वे ग्लोबल बाज़ार के साथ प्रतियोगिता कर सकें।

काँग्रेस की केन्द्रीय सरकार जिस नीति को लाई, बीजेपी सहित तमाम दूसरी संसदीय पार्टियों की राज्य सरकारों ने और तथाकथित मार्क्सवादियों ने भी उत्साहपूर्वक वही रास्ता अपना लिया। कई और भी परिवर्तन किए जो और भी खराब थे। प. बंगाल तथा अविभाजित आंध्र प्रदेश में नो डिटेंशन की नीति लागू कर दी गई, जो कि नई शिक्षा नीति 1986 का ही हिस्सा थी। अंतत: 2009 में खूब ढिंढ़ोरा पीट कर लाया गया शिक्षा का अधिकार कानून (आर.टी.ई. एक्ट) इसमें शामिल कर लिया गया। इसने पढ़ने-पढ़ाने (टीचिंग- लर्निंग) की प्रक्रिया की जड़ों पर ही कुठाराघात किया, नो डिटेंशन की नीति बहुत ही प्रभावकारी ढंग से बच्चों में पढ़ाई के प्रति मोह भंग कर देती है और अंतत: छात्र स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद फिर से गरीब छात्रों का एक बड़ा तबका शिक्षा से दूर हो जाता है। जब एन.डी.ए. की सरकार बनी उस समय बी.जे.पी. शिक्षा में साम्प्रदायिकता को लेकर आई। मूल्य आधारित शिक्षा के नाम पर उन्होंने बहुसख्यक समुदाय के धार्मिक विचारों मनोभावों तथा अंधविश्वासपूर्ण तत्वों को लाकर अब तक बचे-खुचे धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक और वैज्ञानिक शिक्षा के ढाँचे को ही तहस-नहस कर दिया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से साम्रज्यवादी पूँजी से सहायता प्राप्त डी.पी.ई.पी.(डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एडुकेशन प्रोग्राम) तथा एस.एस.ए. (सर्वशिक्षा अभियान) जैसे प्रोजेक्ट भी पेश किए गए जिन्होंने बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी उनके अभिभावकों पर ही लाद दी और सरकारों को निर्देश दिए गए कि वे शिक्षा देने की अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़ा कर लें ताकि कारपोरेट सेक्टर व उसका शिक्षा व्यवसाय फल-फूल सके।

आरएसएस-बीजेपी ने उन्हीं नीतियों का अनुसरण किया

इस व्यापक पृष्ठभूमि में वर्तमान केन्द्रीय सरकार ने सत्ता हासिल की जिसकी लगाम उग्र साम्प्रदायिक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ-बीजेपी गठजोड़ के हाथों में है। जब से ये सरकार में आए हैं तब से शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से ढालने का प्रयास कर रहे हैं। 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रह गई कमियों को सुधारने का बहाना बनाकर ये एक नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन दस्तावेजों पर सरसरी निगाह डालने पर ही वास्तविकता सामने आ जाती है कि वे 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' 86 की नीतियों और कदमों को ही जारी रखना चाह रहे हैं। उन्हें सिर्फ जारी ही नहीं रखा जा रहा है बल्कि और अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा है। निजीकरण-व्यापारीकरण की नीति को जारी ही नहीं रखा जा रहा है बल्कि शिक्षा को अधिकाधिक महंगा किया जा रहा है। हाल ही में बीजेपी-नीत केन्द्रीय सरकार ने डब्ल्यूटीओ के समक्ष 'उच्च शिक्षा' में 'बाजार के प्रवेश' की 'पेशकश' की है। जब इसको लागू किया जाएगा जो यह देश के शिक्षा क्षेत्र को डब्ल्यूटीओ और गैट्स के प्रभाव क्षेत्र में लाया जाएगा और देश की शिक्षा विश्व बाजार के लिए एक पण्य वस्तु के रूप में तब्दील हो जाएगी। और यह आग में घी का काम करेगा तथा पहले से ही बढ़ते स्वच्छंद निजीकरण-व्यापारीकरण को और भी अधिक बढ़ावा देगा तथा अब शिक्षा मात्र केवल गरीबों के लिए ही दुर्लभ नहीं होगी बल्कि सापेक्षत: पैसे वाले लोगों की भी पहुंच से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा का और अधिक व्यापारीकरण होगा। विषय वस्तु को और अधिक विकृत तरीके से व्यवसायीकरण किया जाएगा ताकि वह ग्लोबल बाजार की जरूरतों को पूरा कर सके, एकेडमिक स्वायत्तता, छात्रों, अध्यापकों तथा शैक्षिक संस्थानों के साथ जुड़कर काम कर रहे कर्मचारियों के जनतांत्रिक अधिकारों को तथा स्वतंत्र शोध कार्य के अवसरों को डब्ल्यूटीओ और गैट्स के कड़े दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। वास्तव में ये कदम भारतीय छात्रों, अध्यापकों और देश की जनता तथा ज्ञान और विद्वता के भारतीय शिक्षा व्यवस्था के गौरवपूर्ण इतिहास की कीमत पर भारतीय पूंजी और विदेशी औद्योगिक घरानों के हितों की रक्षा करने और वृद्धि करने के लिए ही उठाए जा रहे हैं।

फिर शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई एक्ट) 2009 में सम्मिलित पास-फेल व्यवस्था को खत्म करने का विध्वंसक निर्णय आया जैसाकि बताया जा चुका है जिसने लगभग पूरी तरह से पढ़ने और पढ़ाने की कर्मशक्ति और इच्छाशक्ति, दोनों को ही तबाह कर डाला है तथा यह आम छात्रों विशेषतौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से आए छात्रों के लिए उच्चशिक्षा के दरवाजे बंद करने की रूपरेखा के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य कर रहा है और यह व्यवस्था आज भी लागू है। जबकि इस नीति को देश के छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों और शिक्षाविदों ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। यह 20 विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा लिखित रूप से सरकार को जमा कराए गए दस्तावेजों से तथा बीजेपी नीत राजस्थान सरकार द्वारा पास-फेल पद्धति को दोबारा लागू करने की घोषणा से साफ झलकता है। इस तथ्य के बावजूद कि मौजूदा केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के दस्तावेज स्पष्टता स्वीकार करते हैं कि स्कूल के छात्र पढ़ने, लिखने और गणना करने के बुनियादी कौशलों को भी नहीं सीख रहे हैं, फिर बीजेपी नीत केन्द्र सरकार इस नीति को वापस लेने में टालमटोल कर रही है और समय बर्बाद कर रही है।

प्रस्तावित नई शिक्षा नीति का नीति दस्तावेज ऐसे तथ्यों से भरा पड़ा है जिससे पता चलता है कि केन्द्र सरकार पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों को ही बढ़चढ़ कर जारी रख रही है जैसे सरकार द्वारा जनता को शिक्षित करने की अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लेना एकरूपता और नियंत्रण आदि स्थापित करने के नाम पर शैक्षणिक कार्यकलापों को नियंत्रित करने के लिए क्षमता के मजबूत केन्द्र स्थापित करना इत्यादि। सरकार के इन कदमों की देश के शिक्षा-प्रेमी लोगों की

(शेष पृष्ठ 4 पर)

वक्त का तकाजा ...

(पृष्ठ 3 का शेष)

तरफ से तीव्र आलोचना हुई क्योंकि सरकार की ये नीतियां शिक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। इसलिए पिछली सरकारों को भी पूरी तरह से इन नीतियों को लागू करने से रोका गया। जबकि मौजूदा सरकार उन्हीं नीतियों में संशोधन करने के नाम पर शब्दाडम्बरों की आड़ में चुपचाप उन्हीं नीतियों को लागू करती जा रही है।

आरएसएस-बीजेपी का छुपा हुआ एजेंडा है-भगवाकरण

लेकिन इससे भी बढ़कर आरएसएस-बीजेपी गठजोड़ जो अब बीजेपी-नीत केन्द्रीय सरकार को संचालित कर रहा है, शिक्षा पर और भी खतरनाक हमले करने में जुटा हुआ है। कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार की कमियों और उसके खिलाफ जनता के उमड़े आक्रोश को धूर्तता से इस्तेमाल करते हुए बीजेपी सरकार हिंदुत्व की अपनी ब्रांडिड अवधारणा के आधार पर आरएसएस-बीजेपी के शिक्षा के भगवाकरण के एजेंडे को लागू करने में लगी हुई है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस एजेंडे को बहुप्रचारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज की आड़ में छुपे तौर पर रखा जा रहा है। जिसके कारण आने वाले दिनों में भारत में शिक्षा के लिए और भी मुश्किल हालात पैदा होने जा रहे हैं। आरएसएस-बीजेपी गठजोड़ ने कॉंग्रेस सरकार की नीतियों का कभी प्रभावी ढंग से विरोध नहीं किया बल्कि उन्हें पूरी तरह स्वीकारा है अब सत्ता में आने के बाद सिर्फ लोग दिखावे की खातिर उनका खण्डन कर रही है।

इसलिए उनका अब कहना है कि पिछली सरकारें जिस शिक्षा को आधुनिक शिक्षा के नाम से लाई थी वह वास्तव में पश्चिमी शिक्षा थी। उन्होंने शिक्षा के भारतीयकरण का नारा दिया और यह ऐसा आह्वान था जिससे राष्ट्रीय उन्माद फैलाकर लोगों को मूर्ख बनाया जा सके। उनका असली मकसद क्या है ये उनके खुद के बयानों से ही स्पष्ट है।

जून 2015 में आरएसएस से संबद्ध हिन्दू शिक्षा बोर्ड के एक सम्मेलन जिसमें राष्ट्रीय मानव संसाधन मंत्री, रेलवे मंत्री, राज्य वित्त मंत्री भी मौजूद थे, उसमें आएएसएस के महामंत्री कृष्ण गोपाल ने शिक्षा के सम्पूर्ण परिवर्तन पर जोर देते हुए कहा कि ''देश की शिक्षा में एकमात्र हिन्दुत्व के विचारों को समावेशित करके ही साधन में पुख्तापन प्राप्त किया जा सकता है और साध्य के भ्रमों का खात्मा किया जा सकता है।''

सितम्बर 2015 में केन्द्र और बीजेपी शासित प्रदेशों के शिक्षा और संस्कृति मंत्रियों की एक मीटिंग में राज्य संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने देश को सांस्कृतिक प्रदूषण से मुक्त कराने और किशोरों को मूल्य आधारित शिक्षा देने के बीजेपी सरकार की योजना के विषय में बताया और कहा कि इस विषय में सरकार इस आलोचना से भी नहीं रुकेगी कि वह आरएसएस की नीतियों को प्रचारित कर रही है।

वह नीति क्या है यह प्राथमिक और सैकेंडरी स्तर पर गुजरात में जो पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू की गई हैं उन्हें देखकर स्पष्ट हो जाता है। जिसमें आरएसएस के एक जानेमाने नीतिज्ञ दीनानाथ बत्रा ने कहा कि शिक्षा के आधुनिकीकरण का अर्थ है शिक्षा का भारतीयकरण न कि शिक्षा का पश्चिमीकरण। और उनका भारतीयकरण धर्म के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है, जैसा कि उनका सोचना है कि 'अपने धर्म के लिए मरना ही सबसे उत्तम है और पराया धर्म ही दुख का कारण है।' (पृष्ठ 118)(बत्रा द्वारा लिखित सीखान नू भारतीयकरण से) इस विषय वस्तु की व्याख्या विभिन्न बिन्दुओं से हुई है। आरएसएस और बीजेपी गठजोड़ अर्थात उनके नेता और कार्यकर्ता आरएसएस और संघ परिवार के हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण के आधार पर ऐतिहासिक मूलग्रंथों को दोबारा से लिख रहे हैं। हालांकि उनके इन प्रयासों की प्रतिष्ठित और नामी इतिहासकारों ने काफी आलोचना की है। आलोचकों का कहना है कि इतिहास लेखन के इस प्रयास में ये न केवल वैज्ञानिक टैम्पर (दृष्टिकोण) को ही छोड़ रहे हैं बल्कि ऐतिहासिक टैम्पर के साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं। वे पौराणिक कथाओं को ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में दर्शा रहे हैं। वे इस तथ्य को छुपा रहे हैं कि पौराणिक कथाओं को इतिहास के रूप में बिना दर्शाते हुए भी अतीत की भारतीय उपलब्धियों पर गर्व किया जा सकता है।

अपने हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण को प्रचारित करने के लिए आरएसएस और बीजेपी गठजोड़ अब स्कूली पाठ्यपुस्तकों को निशाना बना रहा है। नई पाठ्य पुस्तकों यहां तक कि पूर्व प्राइमरी स्कूल स्तर की पाठ्यपुस्तकें अंधविश्वासी विचारों, गलत धारणाओं, भारतीय अतीत के गौरवपूर्ण होने के बेबुनियादी, यहाँ तक कि हास्यास्पद दावों से भरी पड़ी हैं। उनकी प्रेरणा का स्रोत और कोई नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री स्वयं हैं, जिन्होंने यहाँ तक कहा है कि हिंदू देवता गणेश की गर्दन पर लगा हाथी का सिर यह दर्शाता है कि प्राचीन काल में भारतीयों को शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। इनके ऐसे बेतुके हास्यास्पद दावों की लम्बी सूची है जिसे यहाँ देना व्यर्थ है। हालांकि उनमें से एक या दो काफी रोचक हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर दीनानाथ बत्रा द्वारा बच्चों के लिए लिखी पुस्तकों में यह दावा किया गया है कि स्टैम सैल की खोज भारतीयों को हजारों साल पहले पता लग चुकी थी जैसा कि महाकाव्य 'महाभारत' में 100 कौरवों के जन्म से यह सत्यापित हो जाता है। इसके खिलाफ भी शिक्षाविद, प्रोफेसर, अध्यापक और छात्र देश के विभिन्न हिस्सों से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं।

यहाँ तक कि विज्ञान और अतंर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के मंच विज्ञान कॉंग्रेस की गरिमा को एकदम गैर-वैज्ञानिक और छद्म विज्ञान के द्वारा धूमिल कर दिया गया और दावा किया गया कि आधुनिक विज्ञान की खोजें जिनमें कुछ विशेष मूल सैद्धांतिक खोजें भी शामिल हैं उन सब की खोज प्राचीन भारत में हो चुकी थी और यह भी कि हिंदू देवता 'शिव' एक विख्यात पर्यावरणविद थे। विज्ञान कॉंग्रेस में पेश होने वाले दस्तावेज विभिन्न विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभागों से और ऐसे लेखकों से आमंत्रित किए गए जो न कभी किसी प्रकार की गंभीर वैज्ञानिक खोज में लिप्त थे और न ही वे विख्यात वैज्ञानिक रहे थे। स्वयंभू लेखक यहाँ तक भी दावा करने से नहीं चूकते हैं कि वैदिक भारत में उच्च श्रेणी के अंतर-ग्रही विमानों के विषय में जानकारी थी और महाकाव्य महाभारत में होने वाला युद्ध पृथ्वी से आगे बढ़कर चंद्रमा तक और अत: मंगल ग्रह तक फैल चुका था। उन स्थानों पर सैनिक वायुयानों के द्वारा पहुँचते थे। वे दावा करते हैं कि अगर किसी को आइंस्टीन को समझना है तो उसे वेदों को पढ़ना होगा इत्यादि। वास्तव में ही प्राचीन भारत का इतना महिमामंडन देश-विदेश के शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों के द्वारा मजाक और आलोचना का विषय तो बनेगा ही। लेकिन फिर भी आर.एस.एस. और बी.जे.पी. के लोगों का उत्साह कम नहीं होता। अगस्त 2014 में सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने जोर देकर कहा कि अगर मुझे चुनने का अधिकार दिया जाए जो मैं स्कूलों में पहली कक्षा से ही महाभारत और भगवत गीता पढ़ाना चाहूंगा। आई.आई.एम. इंदौर ने भगवत गीता का ज्ञान देने का प्रस्ताव दिया है। संस्थान के एक प्रोफेसर जो साथ ही साथ इस्कॉन के सदस्य भी हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि यह जाना माना धर्मग्रंथ मैनेजमेंट के छात्रों द्वारा उनके निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में उनकी मदद करेगा। जिन राज्य संस्कृति मंत्री के विषय में पहले जिक्र आ चुका है उन्होंने सितम्बर 2015 में कहा था कि संस्कृति मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय जल्दी ही स्कूल-कॉलेजों में रामायण, महाभारत और गीता को पढ़ाए जाने की योजना बनाने पर कार्यरत हैं।

बीजेपी शासित राज्य हरियाणा सरकार ने महाकाव्य महाभारत के युद्धक्षेत्र कुरूक्षेत्र को पावन भूमि के रूप में नामोदित किया है। वहां पर 2015-16 में पहले प्राथमिक कक्षाओं में और बाद में विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में 'गीता' को पढ़ाना प्रारंभ किया है।

यद्यपि आरएसएस-बीजेपी जहां भी सत्ता में है वहां-वहां पर अपने विद्वेषपूर्ण भगवाकरण के विचारों को जनता के बीच में ले जाने के लिए और बच्चों के कोमल दिमागों में इन विचारों को भरने के लिए फतवे जारी कर रही है कि सरस्वती वंदना, भजन, मंत्र और हवन आदि हिंदू धर्म के अनुष्ठानों को सभी शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाए तथा गैर हिंदू छात्रों को भी उन अनुष्ठानों को करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

क्योंकि भारतीयकरण या हिंदूकरण का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से नहीं किया जा सकता है, अत: इसके लिए अंधविश्वास फैलाना, धूर्ततापूर्ण चाल चलना तथा सबसे ऊपर है फतवे का डर दिखाना है। इसके अतिरिक्त और भी विद्वेषतापूर्ण कार्यों के पूर्वसंकेत हैं। उदाहरण के लिए गुजरात में जिस गुजरात ने मौजूदा प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय परिदृश्य पर पहुंचाने के लिए लांचिंग पैड का काम किया था और जो मिस्टर बत्रा की पुस्तकें पढ़ाता है, गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टैक्स्ट बुक्स द्वारा प्रकाशित सोशल स्टडीज़ की पाठ्य पुस्तकें दर्शाती हैं कि लेखकों को भारतीय आजादी आंदोलन में भारी खामियाँ नजर आती हैं और वे फासीवाद और नाजीवाद का महिमामंडन कर रहे हैं।(वैसे भी आरएसएस के लिए यह कुछ नया नहीं है जिसके संस्थापकों और संरक्षकों के यही विचार थे) जहाँ कक्षा आठ के छात्रों को गाँधीजी के असहयोग आंदोलन के नकारात्मक पहलुओं को पढ़ाया जाता है वहीं कक्षा दस की सोशल स्टडीज़ की पाठ्यपुस्तक में 'हिटलर द सुप्रीमो' और 'इंटरनल एचीवमेंट ऑफ नाजीज्म' अध्याय हैं जिसमें भयावह रूप से फासीज्म और नाजीज्म की विवेकहीन तस्वीर पेश की गई है।

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर आरएसएस-बीजेपी के नीतिकार और कार्यकर्ता इस तथ्य से प्रेरित हैं कि एक बार हिटलर ने कहा था कि अगर वह पाठ्यपुस्तकों को नियंत्रित कर पाये तो वह पूरे देश को नियंत्रित कर सकता है। उसका मतलब यह था कि अगर शिक्षा क्षेत्र सीधे-सीधे उसके फासीवादी ढाँचे के तहत आ जाता है तो जनता के सोचने के ढंग को नियंत्रित किया जा सकता है, चिंतन प्रक्रिया को एक साँचे में ढाला जा सकता है और दिमाग को रहस्यवादी अंधविश्वासों, कटटरपन, अंधराष्ट्रभक्ति की तरफ मोड़ा जा सकता है ताकि समाज के फासीवादीकरण के रास्ते को सुगम बनाया जा सके।

इसी प्रकार के मूल्यों को बीजेपी-आरएसएस का गठजोड़ देश के बच्चों में फलीभूत करना चाह रहा है और यह सब शिक्षा व्यवस्था के अंदर की कमियों और खामियों को दूर करने के नाम पर ही किया जा रहा है। ये शिक्षा को दयनीय हालत में मरने के लिए छोड़ देने वाले उग्र विनाशकारी कदम नहीं तो और क्या है!

आर.एस.एस.-बीजेपी का एजेंडा: प्रतिरोध को रोकने के लिए स्वायत्तता पर कठोर हमले

लेकिन शिक्षा पर हमले यहीं खत्म नहीं हो जाते हैं। हमलावर जानते हैं कि उन्हें हर कदम पर प्रतिरोध और आलोचना का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वे अपने एजेंडे को बिना किसी रुकावट के लागू करने के लिए रास्ते को निर्विघ्न बनाना चाहते हैं और उन्होंने वह रास्ता अपनाया भी। उन्होंने आर.एस.एस. के प्रति वफादार लोगों को राष्ट्रीय नीति निर्माण और नियामक संस्थानों जैसे NCERT, ICHR, ICSSR, ASI और शिक्षा संस्कृति और इतिहास के क्षेत्रों में सभी शीर्ष पदों पर आसीन कर दिया।

उन्होंने ICHR की परामर्श कमेटी जो देश-विदेश के 21 विख्यात इतिहासकारों को लेकर बनाई गई थी, को भंग कर दिया। इन विवेकशील इतिहासकारों ने डी.एन. बत्रा द्वारा गुजरात के सेकेण्डरी स्तर की इतिहास की पुस्तक में वर्णित गलत और पूर्ण रूप से अनर्गल विषयवस्तु का विरोध किया था। इसलिए उन्हें निकाल बाहर किया गया और उनके स्थान पर आर.एस.एस. के प्रति वफादार लोगों को बिठा दिया गया जिनका इतिहास के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान भी नहीं रहा। यह प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं हुई।

हाल ही में नई ICHR ने फंडिंग करने के नियमों को बदल दिया। इंडियन हिस्ट्री कॉंग्रेस के उस विशेषाधिकार को खत्म कर दिया जो उसके द्वारा 1972 से उपयोग में लाया जा रहा था तथा इंडियन हिस्ट्री कॉंग्रेस को उसके सालाना अधिवेशन को आयोजित करने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को अगले अधिवेशन के आयोजन के पहले ही बंद कर दिया। सारांश यह है कि लगभग एक साल पहले हिस्ट्री कॉंग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस कथन का विरोध किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा की पद्धति मौजूद थी। इसके खिलाफ हिस्ट्री कांग्रेस ने दिल्ली में आयोजित अपने वार्षिक अधिवेशन में पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक तथ्यों का घालमेल करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए एक प्रस्ताव पास किया था।

इसी प्रकार के कदम इंडियन इंस्ट्च्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट(आई.आई.एम) के अन्दर भी कुशल प्रबंधन लागू करने के नाम पर उठाए गए। इसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार अभी पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त आई.आई.एमों. के गवर्निंग बोर्ड को रद्द करके स्वयं ही संस्थान के नीतिगत मामलों में

(शेष पृष्ठ 6 पर)

1 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद करने का विरोध

भोपाल (म.प्र.) : अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा का गला घोंटते हुए प्रदेश के 1 लाख 8 हजार सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना बनाई है। मतलब प्रदेश के 1 लाख 20 हजार सरकारी स्कूलों में से 90 प्रतिशत स्कूलों को बंद कर शेष बचे 12 हजार स्कूलों को निजी स्कूल की तर्ज पर चलाया जायेगा। और सबसे पहले इस योजना को भोपाल संभाग के 5 जिलों में लागू किया जायेगा। सरकार के इस शिक्षा विरोधी निर्णय के खिलाफ एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) ने 13 फरवरी को स्थानीय शाहजहांनी पार्क पर राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) के प्रदेश सचिव कॉमरेड प्रताप सामल ने कहा कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश का दम्भ भरने वाली प्रदेश सरकार अब हर 15 कि.मी. के दायरे में एक स्कूल रखेगी वो भी निजी स्कूल की तर्ज पर जो मोटी फीस वसूलेंगे। सरकार शराब को घर-घर में पहुंचाने का प्रयास कर रही है लेकिन स्कूल को 15 कि.मी. दूर कर रही है। तब सवाल उठता है कि गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चे मोटी फीस देकर क्या शिक्षा ग्रहण कर पायेंगे? यह नियम साफ तौर पर प्रदेश के लाखों-लाख छात्रों को शिक्षा से वंचित कर देगा। अभी प्रदेश के लाखों बेरोजगार नौजवान संविदा शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, वे लाखों रुपये खर्च करके बी.एड., डी.एड. कर रहे हैं लेकिन सिर्फ 12 हजार स्कूल होने पर जब नई भर्तियां नहीं होंगी तो बेरोजगारी और विकराल रूप धारण कर लेगी और पहले से ही जो लाखों शिक्षक नौकरी में लगे हुए हैं उन्हें भी अलग-अलग बहाने बनाकर रोजगार से बेदखल कर दिया जायेगा। क्या यही है भाजपा के ''अच्छे दिन'' की सौगात? सरकार छात्रों व अभिभावकों को निजी निवेशकों के बेरहम शोषण की चक्की में पिसने के लिए धकेल रही है। आज 90 प्रतिशत सरकारी स्कूलों को बंद कर सरकार बाजार के संकट से जूझ रहे देशी-विदेशी पूंजीपतियों के मुनाफे को सुनिश्चित कराना चाहती है। इस मामले में भाजपा की सरकार भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का ही अनुसरण कर रही है। पार्टी की राज्य कमेटी सदस्या कॉ. रचना अग्रवाल ने कहा कि अगर गांव-गांव में स्कूल बंद होंगे तो सामाजिक माहौल में व्याप्त असुरक्षा और कुसंस्कार व रूढ़िवादिता के चलते सबसे पहले लड़कियों का पढ़ना बंद होगा। क्या छोटी-छोटी बच्चियां व लड़कियां अपने गांव से 15 कि.मी. दूर पढ़ने के लिए जा पायेंगी? क्या यही है '' बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'' नारे की हकीकत! सेव एज्युकेशन कमेटी के प्रदेश संयोजक डॉ. रामअवतार शर्मा ने कहा कि पिछले साल भी सरकार ने 1 लाख 21 हजार सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने का बहाना बनाकर ठेके पर देने का निर्णय लिया था तब छात्रों, शिक्षकों व जनता के भारी विरोध के चलते इसे वापिस लेना पड़ा था। उन्होने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए स्कूल बंद करने की साजिश को नाकाम करना होगा। सभी शिक्षाप्रेमी जनता, छात्रों, शिक्षकों व बुद्धिजीवी वर्ग से चल रहे स्कूल बचाओ-शिक्षा बचाओ आंदोलन को चलाने की अपील की। प्रदर्शन का संचालन डी.एस.ओ. के प्रदेश सचिव सचिन जैन ने किया।

जिला स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजित

इन्दौर (म.प्र.) : बढ़ती अश्लीलता, बच्चियों व महिलाओं के प्रति यौन अपराध और नशाखोरी के खिलाफ 31 जनवरी को ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) का इन्दौर जिला महिला सम्मेलन आयोजत किया गया।

मुख्य वक्ता एआईएमएसएस की राज्य संयोजिका रचना अग्रवाल थी।

संगठन की इन्दौर जिला कमेटी का गठन किया गया। इसमें अर्सी खान को अध्यक्ष, सौम्या सिंह को सचिव, आरती शर्मा को सहसचिव चुना गया। ममता, लता, दुर्गा, छाया, मीना, रेखा, सुनंदा, हंसा व प्रार्थना को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया।

बलात्कारियों को सख्त सजा देने के लिए उठी आवाज

दुर्ग में एआईडीएसओ-एआईएमएसएस का रोष प्रदर्शन

दुर्ग (छ.ग.) : भिलाई शहर में एक सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता युवती ने न्याय नहीं मिलने, केस वापस लेने के दबाव की प्रताड़ना व सामाजिक अपमान के कारण आत्महत्या कर ली। पिछले साल एक सरकारी हस्पताल में भर्ती होने आई इस युवती को बेहोशी का इंजेक्शन लगा कर एक डॉक्टर व दो पुलिस वालों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया था। यद्यपि तीनों आरोपी जेल में हैं लेकिन अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इन आरोपियों ने युवती को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। इस घटना में अपराधियों को सख्त सजा देने आदि मांगों के समर्थन में 5 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दुर्ग कस्बे में ऑल इण्डिया डीएसओ और ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया।

डॉ. एन. ए. करीम की मृत्यु पर एआईएसईसी ने जतायी शोक-संवेदना

4 फरवरी को जारी एक बयान में ऑल इण्डिया सेव एज्यूकेशन कमेटी (एआईएसईसी) ने एआईएसईसी के अध्यक्ष डॉ. एन. ए. करीम की हुई अचानक मृत्यु की खबर पर गहरा दु:ख प्रकट किया। डॉ. करीम ने केरल में उसी दिन बाद दोपहर अन्तिम सांस ली थी। एक जाने-माने वरिष्ठ शिक्षाविद, केरल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रो-वीसी और शिक्षा के हितों और ऐसे ही अन्य सामाजिक मुद्दों के लिए लड़ने वाले जांबाज योद्धा डॉ. करीम हमेशा केरल सहित देश भर में शिक्षा बचाओ कमेटी द्वारा छेड़े गये शिक्षा आन्दोलन की अगली कतार में रहे। अपनी खराब सेहत के बावजूद, वे शिक्षा बचाओ कमेटी के केरल चैप्टर के अगुआ नेता रहे। देश की शिक्षा को डब्ल्यूटीओ-गेटस के प्रावधानों के दायरे से बाहर लाने, इसे वैश्विक बिकाऊ माल न बनाने और शिक्षा का निजीकरण-व्यापारीकरण बिल्कुल बंद करने की मांग पर हाल ही में चलाये गये आन्दोलन का उन्होंने नेतृत्व किया।

इस बहुत बड़ी क्षति की घड़ी में एआईएसईसी डॉ. करीम के शोक-संतप्त परिजनों, दोस्तों और प्रशंसकों के दु:ख में उनके साथ खड़ी है।

प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के खिलाफ शिक्षा बचाओ सम्मेलन आयोजित

जमशेदपुर में शिक्षा बचाओ सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए शिक्षाविद

जमशेदपुर (झारखण्ड) : बीजेपी सरकार की प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के खिलाफ यहां 7 फरवरी को शिक्षा बचाओ सम्मेलन आयोजित किया गया। जाने-माने शिक्षाविद और पटना विश्वविद्यालय के प्रो. विनय कंठ, रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मशहूर स्तम्भकार और लेखक डॉ. रविभूषण, करीम सिटी कॉलेज, जमशेदपुर के प्रोफेसर डॉ. सुभाष गुप्ता और शिक्षा बचाओ कमेटी, बिहार चैप्टर की सचिव साधना मिश्रा वक्ताओं में शामिल थे। कन्वेन्शन की अध्यक्षता अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ कमेटी, झारखण्ड चैप्टर के अध्यक्ष मितेश्वर अग्निमित्र ने की और संचालन कमेटी के राज्य सचिव सुमित राय ने किया।

सभी वक्ताओं ने शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण का एकस्वर में विरोध किया। सभी ने सर्वसम्मति से मांग की कि इस नीति को तुरंत रद्द किया जाये।

आंगनवाड़ी कर्मियों का ऐलान !!!

(पृष्ठ 1 का शेष)

लाभ प्रदान किये जायें। स्कीम वर्करों के लिए 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशें तुरंत लागू की जायें।

आईसीडीएस के मद में केन्द्रीय बजट 2014-15 में 18108 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे जिनमें कटौती करके 2015-16 के केन्द्रीय बजट में सरकार ने 8245.77 करोड़ कर दिये। इससे 27 लाख आंगनवाड़ी सेविकाएं व सहायिकाएं और 10 करोड़ लाभार्थी कुप्रभावित हुए हैं। योजना आयोग, विभिन्न संसदीय कमेटियों, विशेषज्ञ समूहों व संगठनों द्वारा आईसीडीएस व आंगनवाड़ी कर्मियों के पक्ष में सिफारिशें देने के बावजूद, सरकार ने आईसीडीएस के बजट में आधे से भी अधिक कटौती कर दी। इससे समस्त कार्यप्रणाली कुप्रभावित हुई है। आंगनवाड़ी वर्करों व हैल्परों को क्रमश: 3000 रुपये व 1500 रुपये मासिक मानदेय केन्द्र सरकार की ओर से मिलता है, वह भी छह-छह महीने में भुगतान किया जा रहा है। यह बहुत ही मामूली है और वर्ष 2011 के बाद से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है जबकि महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। दूसरी ओर, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासनकाल में लागू किये गये आईसीडीएस मिशन के तहत निजीकरण की गति मौजूदा सरकार ने तेज कर दी है। भिन्न-भिन्न तरीकों से निजीकरण हो रहा है। आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्राइवेट कम्पनियों के हाथों में दिया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में यह ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ।

प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए एआईयूटीयूसी के सर्वभारतीय सचिवमण्डल के सदस्य कॉमरेड अचिंत्य सिन्हा ने कहा कि संयुक्त आन्दोलन वक्त का तकाजा है। इसे जमीनी स्तर तक ले जाना चाहिए। स्थिति के सही अध्ययन के आधार पर सही दृष्टिकोण से इसे संचालित करना लाजिमी है। इसके लिए अनुशासन और उच्च नीति-नैतिकता की दरकार है। आज आंगनवाड़ी कर्मी यहां आई हैं सरकार को यह चेतावनी देने के लिए कि बजट में अगर पिछली गलती को सुधारा नहीं गया, निजीकरण को रोका नहीं गया और वेतन बढ़ोतरी और पेन्शन देने की बात नहीं की गई तो देश भर की आंगनवाड़ी कर्मी आर-पार की लड़ाई लड़ेंगी।

इस विशाल प्रदर्शन को विभिन्न फैडरेशनों की नेत्रियों द्वारा सम्बोधित किया गया। केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन एआईयूटीयूसी की आंगनवाड़ी एम्पलाइज फैडरेशन ऑफ इण्डिया (एफी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चहल, एटक से अमरजीतकौर और इसकी फैडरेशन की ओर से बी.वी. विजयलक्ष्मी, सीआईटीयू की फैडरेशन की ओर से ए.आर. सिन्धु, एचएमएस से एम.ए. पाटिल व चम्पा, इंटक की फैडरेशन से लता यादव, एआईसीसीटीयू की फैडरेशन की ओर से शशि यादव ने सम्बोधित किया। डी. राजा और तपन सेन, दोनों सांसद भी आंगनवाड़ी कर्मियों के समर्थन में बोले।

अगर बजट में उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो देश भर में गांव-शहर में धरने, प्रदर्शन आदि करके 1 मार्च से विरोध सप्ताह मनाने के लिए संयुक्त मोर्चे ने आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं का आह्वान किया।

ऑल इण्डिया केकेएमएस के ब्लाक सम्मेलन आयोजित

तोशाम (भिवानी) : 10 फरवरी को ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन की ओर से गाँव दुल्हेड़ में तोशाम ब्लाक का किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता हरिसिंह दुल्हेड़ी ने की। सम्मेलन में किसान-खेतमजदूरों की समस्याओं और माँगों के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए संगठन के प्रान्तीय सचिव कॉमरेड विजय कुमार ने कहा कि केन्द्र व राज्य, दोनों की ही मौजूदा बीजेपी सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तर्ज पर एक पर एक जनविरोधी नीतियों व कदमों को लागू करके पूंजीपतियों की सेवादार साबित हो चुकी है। इन नीतियों के चलते किसान-मजदूर तबाह हो रहे हैं। किसानों को फसलों के लाभकारी दाम नहीं मिलते। वे कर्ज के बोझ तले दब कर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। मजदूरों को साल भर काम नहीं मिलता है। न सिंचाई का प्रबन्ध है, न बिजली पूरी दी जाती है। बिजली के रेट बेतहाशा बढ़ा दिये गये हैं। फसल खराबे का भी मुआवजा नहीं मिला। अवारा पशुओं का कोई प्रबन्ध न होने से किसान परेशान हैं। इन सब समस्याओं का समाधान जनआन्दोलन से ही सम्भव है। उन्होंने ज्वलंत मांगों पर जोरदार किसान आन्दोलन गठित करने का आहृवान किया।

सम्मेलन को संगठन के जिला प्रधान कॉमरेड जिलेसिंह, जिला सचिव कॉमरेड रोहताश सैनी, राजकुमार, सुखबीर सिंह, आदि ने भी सम्बोधित किया। तोशाम ब्लॉक में किसान संगठन को मजबूत करने और आन्दोलन गठित करने के लिए एक 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जिसका प्रधान राजकुमार और सचिव सुखबीर सिंह को चुना गया।

दुल्हेड़ी : किसान सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कॉ. विजय कुमार

खोल (रेवाड़ी) : 8 फरवरी को ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन का खोल ब्लाक सम्मेलन गाँव निमोठ में हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता अमरसिंह राजपुरा ने की। सम्मेलन में किसान-खेतमजदूरों की समस्याओं और माँगों के बारे में मूल प्रस्ताव पवन कुमार खालेटा ने पेश किया जिसे चर्चा-बहस के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। सभी ने माना कि किसान-खेतमजदूरों की दुर्दशा का कारण सरकार की किसान मजदूर-विरोधी नीतियां हैं। खाद-बीज-तेल-कीटनाशक और औजार आदि खेती में काम आने वाली चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। मनरेगा स्कीम को संकुचित किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य वक्ता संगठन के प्रान्तीय सचिव कॉमरेड विजय कुमार थे। संगठन के जिला सचिव कॉ. रामकुमार, प्रधान जयनारायण, राजबीर, अभय सिंह ने भी अपनी बात रखी और ज्वलंत मांगों पर जोरदार किसान आन्दोलन गठित करने का आहृवान किया।

खोल ब्लॉक कमेटी का गठन किया गया जिसका प्रधान राजकुमार और सचिव अमर सिंह राजपुरा को चुना गया। इसके सदस्य पवन कुमार खालेटा, अभय सिंह जैनाबाद, राजबीर निमोठ, महेन्द्र निमोठ, भंवर निमोठ, रामअवतार पंच निमोठ, कैलाश मनेटी, रामप्रकाश धवाना चुने गये।

एसयूसीआई(सी) म.प्र. राज्य कमेटी द्वारा लगाया गया शिक्षण शिविर

भोपाल में शिक्षण शिविर का संचालन करते हुए कॉ. सत्यवान

भोपाल (म.प्र.) : भोपाल में 12, 13 और 14 फरवरी को एसयूसीआई (सी) की मध्य प्रदेश राज्य कमेटी द्वारा तीन दिवसीय शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के 10 जिलों गुना, ग्वालियर, भोपाल, सागर, जबलपुर, रायेन, इन्दौर, देवास, अशोकनगर, विदीशा के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पिलानी(राजस्थान) से 1, उत्तराखण्ड से 8 सहित 187 कार्यकर्ता इसमें उपस्थित रहे।

शिक्षण शिविर का संचालन पार्टी की केन्द्रीय कमेटी व पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती द्वारा किया जाना था किन्तु उनकी सेहत अच्छी न होने के कारण वे इसमें नहीं आ सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं के नाम भेजे गये अपने संदेश में आशा प्रकट की कि वे सभी उन्नत वैचारिक, सांस्कृतिक व नैतिक स्तर हासिल करने के लिए तथा जनजीवन की जवलंत समस्याओं पर जनआन्दोलन गठित करने के लिए इस शिविर में भाग लेंगे। साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्वबोध की उन्नत भावना से लैस उच्च नैतिक मान रखने वाले न्याप्रिय लोग ही इस रास्ते पर आते हैं और नेताजी सुभाष और भगत सिंह की तरह ऊंचे दर्जे के क्रांतिकारी बनते हैं। इसी के साथ द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की गहरी समझ और मार्क्सवादी दृष्टिकोण जब जुड़ जाता है तो व्यक्तिवादी, निजी संपत्तिबोध पर आधारित सोच से संघर्ष कर पाने से ही कोई व्यक्ति कम्युनिस्ट बनता है। कॉ. चक्रवर्ती की अनुपस्थिति में पार्टी के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. सत्यवान ने शिक्षण शिविर का संचालन किया।

मध्य प्रदेश के राज्य सचिव कॉमरेड प्रताप सामल ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे कम्युनिस्ट चरित्र हासिल करने के अपने संघर्ष को तेज करें, जनता को राजनैतिक रूप से शिक्षित करने के काम में जुट जायें और सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार जन आन्दोलन संगठित करें।

महिलाओं की असुरक्षा व बढ़ते अपराधों के खिलाफ मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

इलाहाबाद (उ.प्र.) : इधर हाल में, लगातार जितनी तेजी से नगर और नगर के आस-पास महिलाओं पर होने वाले अपराधों की घटनाएं बढ़ रही हैं, इससे महिलाओं में भय, असुरक्षा और हताशा बढ़ रही है। शहर की व्यस्त सड़कों पर से, जिस प्रकार सरेआम महिलाओं को घसीट ले जाने की घटनाएं, घर के अन्दर घुस कर उन्हें उठा ले जाने की घटनाएं जितनी तेजी से बढ़ रही हैं, वह बहुत चिंता का विषय है। इस विषय में, ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन तथा ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. के द्वारा 10 फरवरी को जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में मुख्यमंत्री से इस बारे में अविलम्ब कार्रवाई करके स्थिति में जल्द सुधार करने की अपील की गयी। प्रदर्शन में ए.आई.एम.एस.एस. की राज्य अध्यक्ष रश्मि मालवीय के अतिरिक्त ज्ञानशीला शर्मा, राजलक्ष्मी, गीता त्रिपाठी, रेनू, संध्या, निधि सिंह उत्तरा सिंह, सुधा त्रिपाठी, रामपति, उर्मिला शर्मा, वन्दना आदि तथा ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. की राज्य अध्यक्ष झरना मालवीय, विश्वविद्यालय इकाई के उपाध्यक्ष भीम सिंह चन्देल, बृजमोहन, राकेश, हरिकेश, जितेन्द्र आदि शामिल थे।

वक्त का तकाजा ...

(पृष्ठ 4 का शेष)

दिशा-निर्देश दे सकती है और उन दिशा-निर्देश को ही अंतिम भी माना जाएगा।

उपरोक्त कुछ उदाहरण अपने आप में ही यह बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों की स्वायत्तता समाप्त करके अपने एजेंडे को लागू करने का रास्ता साफ कर रही है।

हमले अब सिर्फ शिक्षा पर ही नहीं हो रहे हैं
आम जनता पर भी हमले हो रहे हैं।

यह संक्षिप्त वर्णन भी यह प्रदर्शित करने में कोई शंका नहीं छोड़ता है कि किस प्रकार से भारतीय शिक्षा प्रणाली चौतरफा हो रहे हमलों की वजह से अगाध अंध कार में प्रवेश कर रही है। वही सब पहले की सरकारों द्वारा लागू की जा रही विध्वंसकारी नीतियाँ अभी भी लागू की जा रही है। आम छात्रों के लिए न्यूनतम उचित शिक्षा के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा है। पास-फेल व्यवस्था जिसको खत्म करने की नीति का शिक्षा से संबंधित सभी लोगों ने जिसका विरोध किया था, अभी भी उसे दुबारा से लागू नहीं किया जा रहा है। जबकि नो-डिटेंशन का अर्थ हो रहा नो-स्टडी, जो कि शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता को भयावह तरीके से प्रभावित कर रहा है। शिक्षा के निजीकरण और व्यापारीकरण की नीति पर रोक लगाए बिना, प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या फीस 500 रुपये महीना होनी चाहिए जबकि जरूरतमंद छात्रों को छोड़ कर एक व्यक्ति पर खर्च 2000 रुपये से भी अधिक आता है। स्पष्टत: इससे अत्यधिक फीस वृद्धि होगी। शिक्षा के बाजारोन्मुखी व्यवसायीकरण पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है तथा अधिगम प्रक्रिया को अत्यधिक व्यापारिक बनाने के लिए ग्लोबल बाजार के अनुपातिक योग्यता को विकसित करने का नारा दिया जा रहा है। सभी के लिए जीवंत और प्रभावकारी शिक्षा देने की अपनी जिम्मेदारी से सरकार हाथ खींच रही है। यहाँ तक कि नीति दस्तावेज भ्रामक और विकृत तथ्यों से भरा हुआ है। और इन सबसे ऊपर शिक्षा के उग्र भगवाकरण ने शिक्षा के धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक ढाँचे को भी ध्वस्त कर दिया है।

संक्षेप में सारा वातावरण ही भयानक साम्प्रदायिक सोच से, लाभ कमाने के लिए अधिक से अधिक व्यापारीकरण से, विषय-वस्तु को विरूपित करने के कार्यों से दूषित होता जा रहा है। इसके अलावा अपने निहित एजेंडे को चालाकी से प्रचारित करना और अगर कोई इसकी आलोचना करता है तो उनके खिलाफ तथा अल्पमत धर्म को मानने वालों के खिलाफ असहिष्णु होना भी सम्मिलित है। पूरा माहौल ही अराजक हो गया है। इस हवा में शिक्षा का असल तत्व कहीं खो गया है और इस उपरोक्त वातावरण में शिक्षकों और छात्रों के बीच का आपसी संबंध भी दूषित हो गया है। सत्तासीन राजनैतिक पार्टियों से संबंध रखने वाले छात्र, चाहे वे केन्द्र में बी.जे.पी. से हों या फिर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से ही क्यों न हों, वे मतांतर रखने वाले अध्यापकों पर हमला करने से भी नहीं चूकते हैं। परिणामस्वरूप कुछ अध्यापक भी छात्राओं से उनका कैरियर खराब करने की धमकी देकर बलात्कार करने से भी नहीं चूकते हैं। सरकार इन सबका समाधान खोजने की बजाय हाईटेक डिजिटलाइज्ड शिक्षा को प्रोमोट करने में व्यस्त है जो पैसे वालों के लिए होगी जिसमें अध्यापक और शिष्य के बीच व्यक्तिगत संबंध की बात तो दूर रही आमने-सामने पढ़ने-पढ़ाने से पूरी तरह महरूम होगी। इसलिए ऐसी परिस्थिति में ऐसा एक नजरिया निश्चित ही स्थिति को और भी खराब करेगा। और सर्वोपरि बात यह है कि किसी भी प्रतिरोध को रोकने के लिए और अपनी नीतियों को लागू करने के लिए जो वास्तव में ही एक घातक षड्यन्त्र के तहत लागू की जा रही है। सरकारें प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीकों से शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता का हनन करते हुए पावर का केन्द्रीकरण कर रही है। इसके तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों ही परिणाम खतरनाक होंगे। ई.एफ.ए. ग्लोबल मॉनिटरिंग रिर्पोट 2010 (UNESCO) के अनुसार 128 देशों में भारत का स्थान 105वाँ था। (2001 में भी भारत का स्थान 127 देशों में 105वाँ ही था)

ऐसे एक बिगड़े हुए रूप में समस्त परिदृश्य के साथ लम्बे अर्से में, शिक्षकों और छात्रों या शिक्षा से सरोकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति की, यहां तक कि जनसाधारण की नैतिक रीढ़ टूटने जा रही है। अत: यह स्थिति महज शिक्षा से सरोकार तक ही महदूद रहने वाला मामला नहीं है। यह एक गंभीर विपदा है जिससे देश का आवाम रूबरू है। भावी पीढ़ियों की नैतिक रीढ़ टूट गई तो यह फासीवाद पनपने की उर्वर भूमि बन जायेगी। तब जो एक राज्य में हिटलर, फासीवाद और नाजीवाद की वाहवाही के तौर पर जो शुरू हुआ है, वह आने वाले वर्षों में पीढ़ी दर पीढ़ी पूरे राष्ट्र को पंगु बना देने के लिए देश भर में अपना भद्दा सिर उठा लेगा। नजदीक क्षितिज पर इसके काले बादल मंडरा रहे हैं जो जनवादी दिलो-दिमाग के हर आदमी को इस खतरे को पहचानने और इसका प्रतिरोध करने हेतु आगे आने के लिए पुकार रहे हैं।

देशभर में सम्मान के साथ मनाई गई नेताजी जयंती

मुंगेर

इलाहाबाद

ढकवा, प्रतापगढ़

भारत के आजादी आन्दोलन के महान क्रान्तिकारी नायक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 119वीं जयंती पार्टी और ऑल इण्डिया डीएसओ व ऑल इण्डिया डीवाईओ द्वारा देश के विभिन्न भागों में पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मनाई गई। पिछले अंक में कुछ खबरें छापी गई थी। इस बीच कुछ जगहों से और खबर मिली हैं जिनको हम प्रकाशित कर रहे हैं।

मुंगेर(बिहार): 23 जनवरी को नौवागढ़ स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति पर एआईडीएसओ व एआईडीवाईओ द्वारा नेताजी जयंती पर जुलूस निकाला गया। सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ सभा शुरू हुई। देव आनंद ने 'जिन्दगी की हर शाम गम से भरी' गीत गाया। सभा की अध्यक्षता शिक्षक कैलाश राय ने की। सभा को सम्बोधित करते हुए संगठन के राज्य संयोजक ज्योति कुमार ने कहा कि नेताजी का जीवन-संघर्ष हमारे लिए प्रेरणास्रोत है। राज्य कमेटी के सदस्य रमन सिंह ने नेताजी के अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया। जिला संयोजक रवीन्द्र मंडल ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी, अश्लीलता, फिल्मों में यौनता व हिंसा का प्रदर्शन व शराबखोरी युवाओं को आत्मकेन्द्रित और अपराधी बना रहा है। उन्होंने इनके खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत पर बल दिया। प्रणय मिश्र ने काव्यपाठ किया।

जयपुर (राजस्थान) : एआईडीएसओ और एआईडीवाईओ के संयुक्त बैनर तले 23 से 30 जनवरी तक देश के आजादी आन्दोलन की गैर-समझौतावादी धारा के महानायक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती टोंक फाटक, सांगानेर बाजार, रामपुरा रोड़ सांगानेर, सुभाष चौक, सोडाला, श्रीजीनगर सांगानेर, जगतपुरा जयपुर में गहरी श्रद्धा, बड़े जोश एवं उत्साह के साथ मनाई गई। भारी संख्या में छात्र-नौजवानों ने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। नेताजी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। क्रांतिकारी नारे लगाये गये। नेताजी से सम्बन्धित साहित्य की स्टाल लगाई गई। सभी को नेताजी का बैज लगाया गया। कार्यक्रम के आरम्भ में सुभाष चौक पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई जिसमे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन-संघर्ष पर चर्चा की गई। प्रदीप, गजानन्द, आशीष ने पूरे जोश व श्रद्धा के साथ सारे कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। टोंक फाटक, सुबोध कालेज, महाराजा कालेज के कार्यक्रम में सौरभ व उनके साथियों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। जयपुर में 10 जगहों पर 10,000 पर्चे बांटे गये। श्रीजीनगर में घर-घर जाकर सम्पर्क किया गया। टैम्पो स्टैण्ड पर एक सभा का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रुप में कॉमरेड आर. डी. चौधरी ने नेताजी के जीवन-संघर्ष पर विस्तार से प्रकाश डाला। सभा की अध्यक्षता रमेश यादव ने की। कॉमरेड अजीत शाह ने भी अपनी बात जोशीले शब्दों में रखी। कॉमरेड कुलदीप ने कार्यक्रम का संचालन किया एवं साथ ही क्रांतिकारी गीत गाये।

श्री जीनगर, सांगानेर

इलाहाबाद (उ.प्र.) : प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इलाहाबाद में नेताजी जयन्ती श्रद्धा-सम्मानपूर्वक मनाई गई। सप्ताह भर एआईडीएसओ, एआईएमएसएस व एआईडीवाईओ इलाहाबाद इकाइयों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत नगर के कई स्थानों पर आयोजित इन कार्यक्रमों में नेताजी के चित्र पर पुष्पार्पण कर व्यापक स्तर पर आम जन को बैज पहनाये गये। नेताजी व आजादी आन्दोलन की गैरसमझौवादी धारा के मनीषियों से सम्बन्धित साहित्य भी बेचा गया। आयोजन स्थलों पर नेताजी व अन्य मनीषियों के प्रेरणास्पद उद्धरणों से सजे पोस्टरों की प्रदर्शनी भी लगायी गयी।

नेताजी जयंती के कार्यक्रम का प्रारम्भ, 23 जनवरी को सिविल लाइन्स के सुभाष चौराहे पर नागरिकों को बैज पहनाने से किया गया। बुक स्टाल और पोस्टर प्रदर्शनी भी लगायी गयी। ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की राज्य अध्यक्ष कॉ. रश्मि मालवीय ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में खतरनाक ढंग से उभरते साम्प्रदायिक माहौल में नेताजी के धर्मनिरपेक्ष व धार्मिक सौहार्द सम्बन्धित विचारों को व्यापक जन-मानस तक ले जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम में ज्ञानशीला शर्मा, रेनू, संध्या, राजेश्वरी, उत्तरा सिंह, गीता त्रिपाठी, सुमन शुक्ला, आशू ठाकुर, अंकुश दुबे, भीम सिंह चंदेल, बृजमोहन, राकेश, सिद्धार्थ, नन्द लाल गुप्ता, निर्मल कुमार आदि उपस्थित थे। 23 जनवरी को एआईडीएसओ द्वारा इलाहाबाद विवि परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्रों को बड़ी संख्या में बैज पहनाए गये। नेताजी व अन्य क्रान्तिकारियों से संबंधित साहित्य के प्रति छात्रों में विशेष उत्साह दिखा। महापुरुषों के उद्धरणों से सजे पोस्टर छात्रों का आकर्षण बने।

24 जनवरी को प्रयाग स्टेशन व दारागंज में तथा 31 जनवरी को छोटा बघाड़ा में भी कार्यक्रम आयोजित कर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों को बैज पहनाया गया, साहित्य-विक्रय किया गया तथा पोस्टर प्रदर्शनी लगायी गयी। इसके अतिरिक्त डीएसओ विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा चार दिन विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के सामने कार्यक्रम आयोजित किये गये। साथ ही 29 जनवरी को कौशाम्बी जिले के कटरा गांव में भी बैज पहनाने का कार्यक्रम लिया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र व युवा उपस्थित रहे।

26 जनवरी को चन्द्रशेखर आजाद पार्क में ''आज के समय में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के विचारों का महत्व'' विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में छात्र, युवा व महिलाएं उपस्थित रहे। ए. आई.डी.एस.ओ. के अखिल भारतीय परिषद सदस्य कॉ. दिनेश मोहन्तो तथा एसयूसीआई(सी) के जिला सचिव कॉ. एस.के. मालवीय ने नेताजी के जीवन-संघर्ष पर प्रकाश डाला। संचालन ए.आई.डी.एस.ओ. की राज्य अध्यक्ष कॉ. झरना मालवीय ने किया।

ढकवा प्रतापगढ़ (उ.प्र.) : एआईडीएसओ की ओर से 23 जनवरी को डा. बी.आर. अम्बेडकर शिक्षण संस्थान ढकवा प्रतापगढ़ में आजादी आन्दोलन की गैर समझौतावादी धारा के महान क्रान्तिकारी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के प्रधानाचार्य श्री संजय कुमार यादव ने की तथा संचालन संचिन कुमार ने किया। मुख्य अतिथि अखिलेश कुमार चौधरी थे। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने गीत व भाषण प्रस्तुत किये। हीरालाल भारती (प्रवक्ता हिन्दी), रामकुमार, विजयानन्द, यशवन्त राव, कॉ. जयप्रकाश ने भी अपनी बात रखी।

मनराजी देवी कन्या उ.मा. वि. पठानीपुर सुल्तानपुर में 24 जनवरी को नेताजी जयन्ती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीरेन्द्र कुमार सिंह (पूर्व प्रवक्ता अंग्रेजी) ने की तथा संचालन जयप्रकाश मौर्य ने किया। मुख्य वक्ता कॉमरेड इन्दुकुमार शुक्ला थे और मुख्य अतिथि एसयूसीआई(सी) सुलतानपुर जिला सचिव कॉमरेड जगन्नाथ वर्मा थे। कार्यक्रम में राकेश कुमार मौर्य, सचिव श्रीवास्तव और अंजू मौर्य ने गीत प्रस्तुत किये।

घाटशिला (झारखण्ड) : 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जयंती पर ऑल इण्डिया डीएसओ के बैनर तले घाटशिला में प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें 150 छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रभात फेरी मेन रोड से होते हुए स्टेशन पहुची जहां पर यह सभा में बदल गई। सभा को जिला सचिव कॉ. आशा रानी पाल ने सम्बोधित किया। इस अवसर पर लोगों को नेताजी के बैज पहनाये गये। इस दिन 13 जगहों पर नेताजी जयंती आदरपूर्वक मनाई गई। बाद में पूरे जिले भर में एक सप्ताह तक के कार्यक्रम में 16 जगहों पर नेताजी जयंती मनायी गई।

बिहार राज्य मध्यान्ह भोजन कर्मी संघ का विशाल प्रदर्शन

मुजफ्फरपुर : सभी विद्यालय रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, तत्काल न्यूनतम मजदूरी प्रतिमाह 15 हजार रुपये करने, पेंशन देने, स्वास्थ्य बीमा और मृत्यु बीमा लागू करने, 12 महीने का मानदेय भुगतान करने सहित 15 सूत्री मांगों पर बिहार राज्य मध्यान्ह भोजन कर्मी संघ सम्बन्धित एआईयूटीयूसी के बैनर तले हजारों मिड डे मील वर्करों ने 29 जनवरी को शहीद खुदीराम स्मारक स्थल से समाहरणालय, मुजफ्फरपुर तक प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी को सौंपा।

यूनियन की राज्य नेत्री अनामिका ने कहा कि इस महंगाई के दौर में प्रतिमाह 1250 रुपये देना, वह भी मात्र सलाना 10 माह के लिए, उनके साथ घोर अन्याय है। इसमें उनका गुजारा नहीं होता है।

सभा को एसयूसीआई(सी) बिहार राज्य कमिटी सदस्य कॉ. लालबाबू महतो, बिहार राज्य मध्यान्ह भोजन कर्मी संघ के जिला संयोजक नरेश राम, रंजीत कुमार, कालीकांत झा, हरेन्द्र महतो, रामसेवक पासवान, कृष्णानंदन शुक्ला, मंजू देवी, महेन्द्र साह, हमिदा खातुन, विजय भगत, कुरैसा खातुन, शत्रुघ्न साह, अनिता देवी, उपेंद्र पंडित, छबीला सहनी, रघुनाथ महतो आदि ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता रवीन्द्र चौधरी ने की।

8 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7-8 and 22-23 Fortnightly , Date of Publication : February 20, 2016
सर्वहारा दृष्टिकोण
22 फरवरी, 2016

लघु बचत ब्याज दरें घटाने का एसयूसीआई(सी) ने किया कड़ा विरोध

संयुक्त प्रतिरोधी आन्दोलन खड़ा करने का आह्वान

एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 12 फरवरी को जारी बयान में कहा :

लघु बचत की ब्याज दरों को सरकारी सिक्योरिटिज से कमाई की दरों से जोड़ने और ब्याज दरें हर साल की बजाय हर तिमाही संशोधित करने के केन्द्र सरकार के जनविरोधी फैसले का हम कड़ा विरोध करते हैं। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड, पोस्ट ऑफिस मंथली इन्कम स्कीम, पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपोजिट स्कीम और पोस्ट ऑफिस बचत खाते जैसी स्कीमों में अपनी कष्ट कमाई बचत के तौर पर जमा की हुई है, वे कम रिटर्न मिलने से खत्म हो जायेंगे क्योंकि सरकारी सिक्योरिटिज और अन्य सरकारी प्रपत्रों से कमाई की दर घटने जा रही हैं। यह घोषणा बैंक बचतों पर ब्याज दरों में एक पर एक हुई घटत के समय हुई है। इसलिए, यह साफ जाहिर है कि जहां सरकार डिफाल्टर कंपनियों के ब्याज माफ करने, टैक्सों में भारी कटौती करने और रियायतें देने, औने-पौने दामों पर जनता के खजाने से उन्हें भारी मात्रा में कर्ज देने आदि में बड़े औद्योगिक घरानों और कारपोरेट सेक्टरों के प्रति बेहद उदार है, वहीं यह तेजी से कंगाल और तबाह होते देशवासियों का विभिन्न तरीकों से खून निचोड़ने पर तुली हुई है जो पाश्विक बेदर्दी के साथ मरे हुए को मारने के सिवा और कुछ नहीं है।

हल न हो सकने वाले बढ़ते घोर बाजार संकट की महामारी से ग्रस्त पूंजीवादी व्यवस्था जिसमें शोषित-पीड़ित लोगों की क्रय शक्ति में आ रही उत्तरोत्तर गिरावट की वजह से मांग तेजी से गिरती जा रही है और इस व्यवस्था द्वारा पनपाया गया सर्वग्रासी भ्रष्टाचार भी आग में घी डालने का काम कर रहा है, इसमें शासक पूंजीपति वर्ग और इसकी सरकारें उस संकट के बोझ को आर्थिक बहाली के नाम पर चालाकी से मेहनतकश जनता के कन्धों पर डालने के नित नये-नये बहाने और तरीके खोजने की फिराक में लगी हुई हैं। फलस्वरूप, दुर्दशा और दरिद्रता के मारे हुए लोग पूर्ण तबाही के कगार पर ज्यादा से ज्यादा धकेल दिये गये हैं। जैसा कि अक्सर होता आया है, ऐसे अहम नीतिगत फैसले संसद को दरकिनार कर और बजट से बाहर लिये जा रहे हैं जो कि जनतंत्र के मुखौटे के साथ एक घोर निरंकुश शासन की साफ निशानी है।

यही सही समय है जब देशवासी इस सच्चाई से लैस हों कि शासक पूंजीपति वर्ग और इसकी सरकार के इस ताबड़तोड़ भीषण आर्थिक हमले को रोकने का एकमात्र रास्ता है सही नेतृत्व के तहत और उच्च नीति-नैतिकता व संस्कृति के आधार पर अत्यंत जोरदार संयुक्त संगठित दीर्घकालिक आन्दोलन गठित करना और हर तरह के तुच्छ सोच-विचारों और फूटपरस्ती से ऊपर उठना। वक्त का तकाजा है कि तुरंत उस आन्दोलन की लहर उठे।

एसयूसीआई (सी) बिहार कार्यकर्ता मीटिंग सह शिविर आयोजित

घाटशिला : 3 से 5 फरवरी को मार्क्सवाद-लेनिनवाद शिवदास घोष विचारधारा अध्ययन केन्द्र, घाटशिला में एसयूसीआई (सी) बिहार राज्य के कार्यकर्ताओं की मीटिंग सह शिविर का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को दो पुस्तकें- कॉमरेड शिवदास घोष की 'क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के काम करने का ढंग कैसा हो' तथा कॉमरेड निहार मुखर्जी की 'पार्टी द्वंद्वात्मक प्रक्रिया की उपज'- व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर पढ़कर आने को कहा गया था। पार्टी महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष द्वारा झण्डोत्तोलन तथा कॉमरेड शिवदास घोष की मूर्ति पर मार्ल्यापण के पश्चात् मीटिंग सह शिविर की विधिवत् शुरूआत हुई। कॉमरेड शिवदास घोष की मूर्ति पर पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड रंजीत धर, बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड अरूण कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश राज्य सांगठनिक कमिटी के सचिवमंडल सदस्य कॉमरेड स्वपन चटर्जी तथा अध्ययन केन्द्र के इंजार्च कॉमरेड मलय बोस ने भी मार्ल्यापण किया।

कॉ. प्रभास घोष व रंजीत धर की मौजूदगी में साथियों ने राज्य पार्टी द्वारा दी गयी प्रश्नावली के आधार पर तैयार अपनी व्यक्तिगत रिपोर्ट पेश की। कार्यकर्ताओं ने चर्चा में बेहिचक भाग लिया तथा पार्टी के समक्ष संभावनाओं और समस्याओं को रेखांकित किया। पार्टी के विकास के संबंध में अपने विचारों और सुझावों को पेश करने के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूती प्रदान करने हेतु अपनी आलोचनाएं और आत्म आलोचनाएं भी रखी।

पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड रंजीत धर ने अपने संबोधन में पार्टी के समक्ष विशाल संभावनाओं और बुद्धिजीवी तबकें तथा छात्र-युवाओं में बढ़ते पार्टी समर्थन की चर्चा की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को राजनीतिक पहलकदमी बढ़ाने, जनता के बीच जाने, उनके साथ घुलने-मिलने, उनके दुख-तकलीफों में सहयोगी बनने तथा उन्हें चरित्र द्वारा आकर्षित करने की अपील की। सेल तथा लोकल कमिटी की कार्य प्रणाली पर चर्चा करते हुए कॉमरेड धर ने विभिन्न मुहल्लों व गांवों में पार्टी संगठन निर्माण के लिए सेल व लोकल कमिटी सदस्यों की जिम्मेवारियों के बंटवारे का परामर्श दिया। साथ ही उन्होंने बॉडी संचालन व टीम वर्क की आवश्यकता पर बल दिया।

महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने अपने समापन भाषण में एसयूसीआई (सी) के निर्माण के दौरान कॉमरेड शिवदास घोष तथा उनके मुट्ठीभर सहयोगियों द्वारा चलाये गये कष्टसाध्य संघर्षों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पार्टी निर्माण के दौर में तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई को महान स्तालिन व माओ-त्से-तुंग का समर्थन प्राप्त था। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक, अनुशीलन समिति का गौरव लिये हुए आरएसपी तथा रवीन्द्रनाथ टैगोर के परिवार के सौमेन्द्र नाथ ठाकुर की आरसीपीआई की ताकतवर मौजूदगी थी। उन्होंने पार्टी के विकास के लिए पैदा हुई अनुकूल स्थिति तथा देश के करीब-करीब सभी राज्यों में पार्टी गतिविधियों के विस्तार पर भी चर्चा की। उन्होंने पार्टी संगठन निर्माण

घाटशिला में कार्यकर्ता मीटिंग का संचालन करते हुए कॉ. प्रभास घोष

के लिए इस स्थिति का फायदा और इसके लिए सर्वहारा नैतिकता व संस्कृति को अपनाते हुए पूंजीवादी संस्कृति, पूंजीवादी मानसिकता और पूंजीवादी विचार पद्धति से मुक्त होने की अपील की। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को कॉमरेड शिवदास घोष की रचनाओं को बारीकी तथा आलोचनात्मक ढंग से अध्ययन और उन्हें अपने जीवन में प्रयोग करने का परामर्श दिया। यह बताते हुए कि विश्व पूंजीवाद-साम्राज्यवाद अभूतपूर्व संकटों से ग्रस्त है, उन्होंने कहा कि बाजार अर्थव्यवस्था का आज कोई बाजार ही नहीं है। लगातार मंदी जारी है। अपने देश के बारे में उन्होंने कहा कि यहां पूंजीवाद और ज्यादा केन्द्रीभूत हुआ है। एकाधिकारी पूंजी बहुराष्ट्रीय पूंजी में तब्दील हो चुकी है। दूसरी तरफ भयंकर शोषण जारी है। यहां-वहां प्रस्फुटित हो रहे जन असंतोषों, जन उभारों तथा सही नेतृत्व व सही विचारधारा की अनुपस्थिति की वजह से उनकी असफलताओं को दर्शाते हुए उन्होंने कॉमरेडों को आगे आने और कॉमरेड शिवदास घोष विचार के मार्ग-दर्शन में इन जन उभारों को पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति की दिशा में संचालित करने की अपील की।

शिविर में पैदा हुआ उत्साहपूर्ण माहौल स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय गीत के साथ शिविर का समापन हुआ।

बिहार पार्टी का सचिवमंडल गठित

घाटशिला : एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष तथा पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड रंजीत धर की मौजूदगी में मार्क्सवाद-लेनिनवाद शिवदास घोष विचार अध्ययन केन्द्र, घाटशिला में 5 फरवरी को निम्नलिखित कॉमरेडों को लेकर पार्टी के बिहार राज्य सचिव मंडल का गठन किया गया।

1. कॉ. शिव शंकर
2. कॉ. अरूण कुमार सिंह
3. कॉ. साधना मिश्रा
4. अर्जुन कुमार
5. राजकुमार चौधरी
6. उमा शंकर वर्मा

केरल में एआईएसईसी ने की शिक्षा बचाओ जन बैठक

इन्टरनेशनल हायर एज्यूकेशन जोन(आईएचईजैड) स्थापित करने के विचार को पनपाने और बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक शिक्षा बैठक केरल के कोवलाम, तिरुअनंतपुरम में 29-30 जनवरी को हुई थी। आईएचईजैड जन शिक्षा को, खासकर विश्वविद्यालय शिक्षा सहित उच्च शिक्षा को और भी संकुचित करने का पूंजीपतियों द्वारा सुनियोजित हथकण्डा है। जमीन और ऐसी ही अन्य कुछ पूर्वशर्तें पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति आईएचईजैड खोल सकता है। पढ़ाये जाने वाले कोर्स उन कौशलों को विकसित करने के लिए पैटर्न किये जायेंगे जो मानवीय गुणों व चरित्र को विकसित करने की बजाय बाजार की जरूरतों को पूरा करेंगे। सब्सिडी देकर सस्ती दरों पर सरकार उनको बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करेगी। उच्च शिक्षा के कफन में आखिरी कील ठोंकने के लिए पूर्वनिर्दिष्ट आईएचईजैड शिक्षा को एक 'व्यापार करने लायक बिकाऊ माल' मानने की धारणा पर आधारित हैं।

शिक्षा के वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी सारतत्व पर लगातार हमला किया जा रहा है और इस सारतत्व से वंचित किया जा रह है। इसके खिलाफ प्रतिवाद में, ऑल इण्डिया सेव एज्यूकेशन कमेटी (एआईएसईसी), केरल चैप्टर की पहल पर 29 जनवरी को सचिवालय के सामने एक जन शिक्षा बैठक आयोजित की गई। इसने वैश्विक ग्लोबल शिक्षा बैठक का बायकाट करने की अपनी मांग जोर शोर से एकस्वर में उठाई।

जाने-माने पत्रकार बीआरपी भास्कर ने जन शिक्षा बैठक का उद्घाटन किया। एआईएसईसी के राज्य सचिव एम शजरखान ने जनवादी शिक्षा के अधिकार की घोषणा प्रस्तुत की और डॉ. वी. वेणुगोपाल ने इसका अनुमोदन किया जबकि एआईडीएसओ के अध्यक्ष ई.एन. शांतिराज और प्रो. पी.एन. थंकाचन आदि ने भी इस अवसर पर सभा को सम्बोधित किया।

"Print-line
Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."
Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com
फोन नं. : 011-25726631, 9868350503